which were sufficient to take care of export commitments for the year 1988-89. This resulted in reduced procurement of iron ore by MMTC for export duiing 1988-89.

(c) Market diversification, offer of incentive process for shipments from Para-dip port, improvement in infrastructure at ports etc. are some of the steps taken| proposed to be taken to increase off take of iron ore.

बंजर भूमि का विकास

@1603. **श्री सत्य पाल मलिक :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बंजर भूमि के इस्तेमाल को बढ़ाने के कार्यक्रमों में कितनी प्रगति हुई है और क्या गैर-सरकारी क्षेत्र के लोगों ने बंजर भूमि के विकास के लिए पहल करने की पेशकश की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की नीति क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जेड० आर० अन्सारी) : (क) परती भूमि विकास की नीति का उद्देश्य वनीकरण एवं वृक्षारोपण द्वारा देश की परती भूमि को उत्पादन योग्य बनाना है । विगत तीन वर्षों के लक्ष्य एवं उपलब्धियां निम्नप्रकार हैं :—

वर्ष	लक्ष्य (क्षेत्र मिलियन हैक्टेयर में)	उपलब्धि
1985-86	1.45	1.51
1986-87	1.71	1.76
1987-88	1.79	1.77

वर्ष 1988-89 के लिए 2 मिलियन हैक्टेयर का लक्ष्य है ।

@ पूर्वतः अतारांकित प्रश्न 442, 29 जुलाई, 1988 से स्थानान्तरित ।

उपरिलिखित उपलब्धियों के अन्तर्गत किसानों एवं स्वैच्छिक एजेंसियों, जिन्होंने परती भूमि विकास के लिए पहल की है, द्वारा किए गए प्रयास शामिल हैं ।

वनों पर आधारित कुछ उद्योगों ने अपनी कच्चे माल की जरूरतों को पूरा करने के लिए निजी प्रयोग हेतु वृक्ष उगाने के लिए परती भूमि का विकास करने की पेशकश की है ।

(ख) वर्तमान नीति स्वैच्छिक एजेंसियों के माध्यम से फार्म वानिकी और परती भूमि विकास को निम्नप्रकार से प्रोत्साहित करती है :—

(i) पौधों का मुफ्त/इमदादी दर पर वितरण ।

(ii) विकेन्द्रित जन-पौधशालाओं को प्रोन्नत करना ।

(iii) परती भूमि विकास/वनीकरण प्रायोजनाओं और जागरूकता एवं प्रशिक्षण संबंधी कार्यकलापों को आरम्भ करने के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों को अनुदान देना ।

(iv) वृक्ष उत्पादक सहकारिताओं को बढ़ावा देना ।

(v) फार्म के अन्दर सिल्वी चारागाह विकास के लिए छोटे एवं सीमान्त किसानों को सहायता प्रदान करना ।

(vi) निकृष्ट सार्वजनिक भूमि पर भूमिहीन, लघु एवं सीमान्त किसानों के लिए वृक्ष पट्टा परियोजना ।

उद्योगों को अपने प्रयोग हेतु वृक्ष उगाने के लिए वन भूमि उपलब्ध कराना सरकार की नीति नहीं है ।